

अगर आप अपने विचार नहीं बदलेंगे तो परिणाम भी नहीं बदलेंगे।
- अज्ञात



हटया भी जाए तो चरणबद्ध तरीके से

सांसदों की यह भी राय थी कि राहत कार्यों को लेकर सरकार की जो नीतियां हैं, उनका ठीक से प्रचार किया जाए ताकि जरूरतमंद उसका लाभ ले सकें। कोरोना के खिलाफ संयुक्त रणनीति बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश के जिम्मेदार लोगों से बात कर रहे हैं।

राधा जोशी।

देश की अधिकतर राजनीतिक पार्टियां अभी लॉकडाउन को पूरी तरह हटाने के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि इसे हटाना भी जाए तो चरणबद्ध तरीके से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संसद के दोनों सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने पांच मांगें रखी गईं, जिनमें बजट घाटे के लिए निर्धारित राज्य एफआरबीएम सीमा को 3 से बढ़ाकर 5 फीसदी करने, राज्यों को उनका बकाया जल्दी देने, राहत पैकेज को जीडीपी के एक फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करने, कोरोना टेस्ट को फ्री करने और पीपीई समेत सभी मेडिकल इविवपमेंट मुहैया कराने की बात शामिल है। ज्यादातर

नेताओं का मानना था कि लॉकडाउन के सकारात्मक नतीजे निकले हैं, लेकिन संक्रमितों की संख्या अब भी लगातार बढ़ रही है लिहाजा इसे अभी नहीं बल्कि धीरे-धीरे करके ही हटाया जाए। पहले इसे ग्रामीण इलाकों से हटाया जाए क्योंकि कई इलाकों में फसल कटाई का काम आगे नहीं टाला जा सकता। शहरों में भी अधिक प्रभावित क्षेत्रों में बाद में हटाया जाए, कम प्रभावित इलाकों में शुरू में हटाया जा सकता है। सांसदों की यह भी राय थी कि राहत कार्यों को लेकर सरकार की जो नीतियां हैं, उनका ठीक से प्रचार किया जाए ताकि जरूरतमंद उसका लाभ ले सकें। कोरोना के खिलाफ संयुक्त रणनीति बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश के जिम्मेदार लोगों से बात कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पूर्व

राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी दलों के कई नेताओं से बातचीत की थी और बीते दो अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया था। अभी के माहौल में प्रधानमंत्री को व्यापक राजनीतिक दायरे से सलाह लेनी चाहिए और वहां से आ रहे सुझावों पर विचार करना चाहिए, चाहे वे किसी की भी तरफ से आए हों। पिछले दिनों सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर पीएम को कुछ सुझाव दिए लेकिन कई वरिष्ठ बीजेपी नेता तुरंत उनकी आलोचना में जुट गए। किसी व्यक्ति की मंशा पर सिर्फ इसलिए सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए कि वह विपक्ष का है। सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर कहा कि सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों का खर्च

बचाया जाए। उन्होंने 20,000 करोड़ की लागत से किए जा रहे 'सेंट्रल विस्टा' ब्यूटीफिकेशन एवं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को स्थगित करने, सरकार के खर्च कम करने, नेताओं की गैर जरूरी विदेश यात्राओं पर रोक लगाने और 'पीएम केयर्स' फंड की संपूर्ण राशि को 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष' ('पीएम-एनआरएफ') में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया और इससे बचने वाली राशि को कोरोना से लड़ने और कमजोर तबकों को मदद पहुंचाने में लगाने को कहा। इस तरह के सुझावों पर सहमत होना या न होना सरकार की पसंद पर निर्भर करता है। सरकार इन सुझावों को नहीं मानती है तो न माने, लेकिन फिलहाल तो अपने दरवाजे सभी आवाजों के लिए खुले रखे।

जीवन

अशोक वोहरा।
अगर आप अपने चारों ओर देखें तो पता चलता है कि हर व्यक्ति दासता में जीवन व्यतीत कर रहा है। अपने जख्मों को सुदूर शब्दों में छिपा रहा है।

धर्म-दर्शन



जड़े तभी मजबूत होंगी जब हम जो हम करते आ रहे हैं, अगर उसे करना बंद कर दें। अब तक जो करते आ रहे हैं, केवल उसका उल्टा करें। हर बच्चे को सोचने का मौका दिया जाना चाहिए। हमें उसे उसकी बौद्धिकता को तेज करने में मदद करनी चाहिए। हमें उसे परिस्थिति और अवसर देने में मदद करनी चाहिए जहां वह खुद के बारे में स्वयं निर्णय ले सके। हमें इसे एक बिंदु बनाना चाहिए कि किसी को भी आज्ञाकारी बनने के लिए जोर ना डाला जाए और हर किसी को आजादी की बागवानी और खुबसूरती सिखाई जाए। तभी जड़ मजबूत होगी।

संपादकीय

डरा रहे ये केस

थोड़ा और पीछे चलकर हम पहुंचते हैं 2005 में, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश गर्मियों की छुट्टियों में टैक्सस स्थित अपने रैंच में थे। उस दौरान आई एक किताब 'द ग्रेट इंप्लूएंजा' की एक एडवांस प्रति राष्ट्रपति के पास पहुंची। किताब के लेखक थे इतिहासकार जॉन एम बैरी। 2004 में प्रकाशित यह किताब 1918 में दुनिया भर में फैले स्पैनिश फ्लू के बारे में थी, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। बुश ने पढ़ना शुरू किया तो बिना खत्म किए रख नहीं पाए। जब वह वापस वॉशिंगटन लौटे तो आंतरिक सुरक्षा मामलों की शीर्ष सलाहकार फ्रैन टाउनसैंड को तलब किया और कहा कि उन्हें भी यह किताब पढ़नी चाहिए। यहीं से शुरुआत हुई अमेरिका द्वारा किसी महामारी से निपटने की विस्तृत योजना के निर्माण की। आज जिन नियमों का पालन अमेरिका में किया जा रहा है उनकी जमीन पंद्रह साल पहले बुश के शासनकाल में तैयार की गई थी। अमेरिकी चैनल एबीसी न्यूज ने फ्रैन टाउनसैंड के हवाले से कहा है कि बुश किसी महामारी की आशंका को लेकर इतने गंभीर थे कि इस मुद्दे को उन्होंने खत्म नहीं होने दिया। बताते हैं कि बुश के कई सलाहकारों ने महामारी को लेकर बुश की राय को बहुत महत्व भी नहीं दिया था लेकिन बुश अड़े रहे और नवंबर के महीने में उन्होंने एक विस्तृत प्रस्ताव रखा। इसकी तैयारियों के लिए उन्होंने सात अरब डॉलर की राशि अलग रखी और अपने सचिवों से इसको गंभीरता से लेने को कहा। उस समय बुश ने चेतावनी दी थी कि अगर हम महामारी का इंतजार करेंगे तो वह हमें तैयारी का समय नहीं देगी।

ऐसे सवाल हैं जिनकी तह में जाने पर पता चलता है कि कैसे एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने वक्त रहते एक बड़े खतरे को पहचाना था और उससे निपटने की तैयारी भी की थी, लेकिन सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं।

निपटने के लिए तैयार नहीं

जे. सुशील।

कोरोना वायरस के आने के बाद से बार-बार कहा जा रहा है कि कोई भी देश ऐसी आपदा से निपटने के लिए तैयार नहीं था और इसका इतना अप्रत्याशित होना ही वह कारण है, जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग हॉलिवुड फिल्म कांटेजियन का भी हवाला दे रहे हैं कि वर्ष 2011 में ही ऐसी बीमारी की कल्पना हॉलिवुड ने कर ली थी। लेकिन क्या कल्पना हवा में होती है। क्या कल्पनाओं का कोई आधार नहीं होता? क्या ऐसी बीमारी फैलने का अंदाजा किसी को भी नहीं था? और था तो किसी ने इस बारे में कोई तैयारी क्यों नहीं की? ये ऐसे सवाल हैं जिनकी तह में जाने पर पता चलता है कि कैसे एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने वक्त रहते एक बड़े खतरे को पहचाना था और उससे निपटने की तैयारी भी की थी, लेकिन सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। किसी वायरस से लोगों की मौतें होने का परिदृश्य नया नहीं है। अब से पांच साल पहले, मार्च 2015 में टेड टॉक देते हुए बिल गेट्स ने कहा था कि अगले कुछ दशकों में अगर किसी एक घटना में दस लाख या उससे अधिक लोग मरते हैं तो वह किसी वायरस के कारण होगा, मिसाइलों के कारण नहीं। इसलिए दुनिया को इस दिशा



में सोचना चाहिए।

उनकी वह अविश्वसनीय बात ठीक पांच साल बाद सच साबित हो रही है और जाहिर है, इससे बिल गेट्स बहुत खुश नहीं हैं। गेट्स फाउंडेशन पिछले कई सालों से स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर काम कर रहा है और संभवतः इस क्षेत्र में उनकी जानकारी ने ही उन्हें इस तरह के परिदृश्य पर सोचने के लिए विवश किया होगा। अब इससे पीछे चलते हैं। फिल्म कांटेजियन 2011 में बनी थी और फिल्म में दिखाए गए हालात तकरीबन आज जैसे ही हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका को पहले ऐसी स्थिति के बारे में कोई भान नहीं था। 2009 में ओबामा प्रशासन आया तो पुराने प्रशासन ने नए निजाम के लोगों को हर तैयारी के

बारे में बारीकी से ब्रीफ किया जिसमें सरकार से जुड़े सारे गंभीर मसले शामिल थे। इन लंबी बैठकों का लाभ यह हुआ कि बुश से ओबामा प्रशासन का ट्रांजिशन बेहतरीन तरीके से हुआ। ओबामा ने इस रवायत को जारी रखा और जब ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए तो ओबामा प्रशासन ने नए प्रशासन के लोगों को हर तरह की जानकारी मुहैया कराने की कोशिश की। जानी-मानी वेबसाइट पोलिटिको ने हाल में इस बारे में जारी एक रिपोर्ट में बताया है कि महामारी से जुड़ी ब्रीफिंग में ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ सलाहकार मौजूद नहीं थे और उनका रवैया बहुत ही हल्का रहा था।

ओबामा के शासनकाल में महामारी से निपटने के लिए एक प्लेबुक तैयार की गई थी कि महामारी फैले तो क्या-क्या कदम उठाए जाएं। महामारी के मामले को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जोड़ा गया था और उसके लिए काउंसिल में हेल्थ यूनिट बनाई गई थी। यह प्लेबुक 2016 में इबोला महामारी के मद्देनजर तैयार की गई थी लेकिन पोलिटिको के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इतना ही नहीं, 2018 में ट्रंप प्रशासन ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की हेल्थ यूनिट को ही भंग कर दिया जिसकी जिम्मेदारी ऐसी किसी महामारी में लीड करने की थी। कुल मिलाकर, ओबामा के समय बनी इस प्लेबुक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

सूडोकू नवताल-5310				* * * * *			
		2				3	
		9		8		2	6 4
1				3	6		9
4		3					
		8		2			1
						8	6
		4		7	5		3
		3	7	5		4	1
		2				8	

सूडोकू नवताल-5309 का हल			
4	6	2	3
8	1	7	9
3	5	9	1
6	4	1	5
2	7	5	8
9	3	8	2
1	2	3	6
5	9	4	7
7	8	6	4

अपना ब्लॉग

कोरोना का कहर रती

भर भी थामा नहीं

मोहन। 2019 में ट्रंप प्रशासन ने किसी ऐसी महामारी की आशंका को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया और न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार इस ट्रेनिंग में कई परिदृश्य ऐसे थे जो आज बिल्कुल हबहू अमेरिका के सामने हैं। कहते हैं कि उस समय कल्पना की गई थी कि वायरस चीन से आएगा और अमेरिका में मेडिकल स्प्लाई की भारी कमी रहेगी। यह सब आज हम अपने सामने घटित होता हुआ देख रहे हैं। ऐसी तैयारियों के बावजूद कोरोना का कहर रती भर भी थामा नहीं जा सका तो इसके लिए आलोचक ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिन्होंने मार्च के पहले हफ्ते में कोरोना को डेमोक्रेटिक पार्टी का 'होक्स' करार दिया था। हालांकि तब से लेकर अब तक ट्रंप अपने व्यवहार में काफी बदले हैं लेकिन अमेरिका को इस बीच काफी नुकसान हो चुका है, जिसकी भरपाई फिलहाल तो संभव नहीं दिख रही है।

मंदिर वहीं
बनाएंगे *

* ऑफर केवल यूपीके लिए.
* ऑफर केवल मतदान की
तारीख तक वैध.

